



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1936 (श0)
(सं0 पटना 528) पटना, बुधवार, 25 जून 2014

सं0 अ0पा0-187/2012—562/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

25 जून 2014

विषय:- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना का हस्तान्तरण एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत किए जाने पर स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संलेख संख्या-4407 वि(2) दिनांक 26.06.2007 में सन्निहित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.07.2007 में मंत्रिपरिषद द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना की स्वीकृति तथा इसके लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।

2. इस परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति “जीविका” का गठन किया गया, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन निर्बंधित की गई है । समिति का प्रशासनिक नियंत्रण वर्तमान में वित्त विभाग के अन्तर्गत है ।

3. वित्त विभाग के पत्रांक-357 दिनांक-09.05.2008 द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना तथा इसके लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना की कुल लागत US\$ 73 मिलियन (306.6 करोड़ रु०) की थी । यह परियोजना 5 वर्षों की थी । यह परियोजना राज्य के 6 जिलों यथा नालंदा, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं पूर्णियाँ के कुल 42 प्रखण्डों में विश्व बैंक के सहयोग से अक्टूबर 2007 में निर्धनता निवारण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी ।

इस परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व वित्त विभाग के पत्रांक-409 दिनांक 29.03.2012 द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना अतिरिक्त वित्तीय सहायता कुल लागत राशि 741 करोड़ रु० की स्वीकृति प्रदान करते हुए तीन वर्षों की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई तथा चयनित 6 जिलों के सभी प्रखण्डों में विस्तारित परियोजना लागू की गई ।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) लागू करने के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (BRLPS) को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के अधीन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि के संभावित स्त्रोतों में विश्व बैंक सम्पोषित बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना अतिरिक्त वित्तीय सहायता की राशि 741 करोड़ ₹0 रखी गई है। इस क्रम में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना ग्रामीण विकास से संबंधित होने के कारण जीविका का प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग के अधिन किया जाना सरकार के विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना का हस्तान्तरण एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामेश्वर सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 528-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>